भारत सरकार

भारी उद्योग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2714

02 अगस्त, 2022 को उत्तर के लिए नियत

इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमत

2714. श्री जगदम्बिका पाल:

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का आम आदमी के बजट को ध्यान में रखते हुए इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) की कीमत को पेट्रोल वाहनों (पीवी) की कीमत से कम करने का कोई विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने 2030 तक इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाना सुविधाजनक बनाने के लिए कोई नई पहल की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार का विचार बसों और ऑटो रिक्शा सहित सार्वजनिक परिवहन के पूरे बेड़े को इलेक्ट्रिक फ्लीट में बदलने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

भारी उद्योग राज्य मंत्री

(श्री कृष्ण पाल गुर्जर)

(क): महोदय, इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमत कम करने और इलेक्ट्रिक वाहनों के अंगीकरण को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने देश में निम्नलिखित कदम उठाए हैं :

i. फेम इंडिया स्कीम के दूसरे चरण के तहत दिनांक 11 जून, 2021 से इलेक्ट्रिक दुपहिया वाहनों के लिए मांग प्रोत्साहन को वाहन लागत सीमा के 20% से बढ़ाकर 40% अर्थात् 10,000 रुपये/किलोवाट घंटे से बढ़ाकर 15,000 रुपये/किलोवाट घंटे कर दिया गया है। इस प्रकार, इलेक्ट्रिक दुपहिया वाहनों की लागत आईसीई दुपहिया वाहनों के बराबर हो गई है।

ii. सरकार ने देश में बैटरी की कीमतों को कम करने के लिए देश में उन्नत रसायन सेल (एसीसी) के विनिर्माण हेतु उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम को दिनांक 12 मई, 2021 को स्वीकृति दी। बैटरी की कीमत में गिरावट से इलेक्ट्रिक वाहनों की लागत में कमी आएगी।

iii. ऑटोमोबिल और ऑटो घटकों के लिए उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम के अंतर्गत इलेक्ट्रिक वाहनों को भी शामिल किया गया है। इस स्कीम को 25,938 करोड़ रुपये के बजटीय परिव्यय से दिनांक 15 सितंबर, 2021 को पाँच वर्ष की अवधि के लिए अनुमोदित किया गया था।

iv. इलेक्ट्रिक वाहनों पर वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) को 12% से घटाकर 5% और इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जर/चार्जिंग स्टेशनों पर जीएसटी को 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है।

v. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने घोषणा की है कि बैटरी से चलने वाले वाहनों को हरे रंग की लाइसेंस प्लेट दी जाएगी और उन्हें परमिट लेने की आवश्यकता नहीं होगी।

vi. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर राज्यों को इलेक्ट्रिक वाहनों पर पथकर माफ करने की सलाह दी है जिससे इलेक्ट्रिक वाहन की शुरुआती लागत को कम करने में मदद मिलेगी।

(ख) और (ग): महोदय, ऐसा कोई प्रस्ताव भारी उद्योग मंत्रालय में विचाराधीन नहीं है।

***